

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4570
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

उद्योगों में बिजली की खपत

4570. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में वार्षिक वृद्धि दर के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बिजली की मांग में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;
- (ग) क्या प्रत्येक राज्य बिजली की आपूर्ति और मांग को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) देश में प्रत्येक वर्ष उद्योगों और घरों द्वारा खपत की जाने वाली बिजली की कुल मात्रा कितनी है; और
- (ड) क्या उद्योगों और घरों में बिजली की खपत के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की वर्षवार खपत का व्यौरा, जो मार्च, 2018 से मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ख) : पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। अनुबंध-II के अनुसार, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता का व्यौरा, इस अवधि के दौरान 5% की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) दर्शाता है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति स्कीम (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी भारत सरकार की स्कीमों के कार्यान्वयन से विद्युत की पहुंच में काफी सुधार हुआ है और देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरों को विश्वसनीय और निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा, तेजी से आर्थिक विकास, शहरीकरण, बढ़ते जीवन स्तर और एयर कंडीशनर, अन्य उपकरणों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे ऊर्जा-

गहन उपकरणों के बढ़ते उपयोग जैसे कारक इस मांग में और योगदान करते हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित ऊष्णता वृद्धि और अस्थिर मानसून वर्षा भी विद्युत की बढ़ती मांग में योगदान करती है।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों का सहयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिह्नित किए गए घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी परिवारों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। सभी राज्यों में पीएम-जनमन के अंतर्गत चिह्नित किए गए पीवीटीजी परिवारों और डीए-जेजीयूए के अंतर्गत चिह्नित किए गए आदिवासी परिवारों सहित 10,19,030 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 21.9 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

(ग) : यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।

सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई।

(घ) और (ङ) : वित वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक देश में उद्योगों और घरों द्वारा खपत की गई विद्युत का व्यौरा, जिसमें इस अवधि के दौरान वृद्धि दर भी टर्शाई गई है, अनुबंध-III पर दिया गया है।

मार्च, 2018 से मार्च, 2024 तक देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की वर्षवार खपत तथा वार्षिक वृद्धि दर का विवरण

वित्त वर्ष	प्रति व्यक्ति खपत (किलोवाट घंटा)	वार्षिक वृद्धि दर (%)
31.03.2018	1,149	
31.03.2019	1,181	2.79
31.03.2020	1,208	2.29
31.03.2021	1,161	-3.89*
31.03.2022	1,255	8.10
31.03.2023	1,331	6.06
31.03.2024	1,395	4.81

* कोविड समय

लो.स.अतारां.प्र.सं.-4570

अनुबंध-II

ऊर्जा आवश्यकता का विवरण जिसमें वृद्धि दर और चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाया गया है

वित्त वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	विकास %	सीएजीआर
	(एमयू)	%	%
2018-19	12,74,595		5.0
2019-20	12,91,010	1.29	
2020-21*	12,75,534	-1.20	
2021-22	13,79,812	8.18	
2022-23	15,13,497	9.69	
2023-24	16,26,132	7.44	

*कोविड समय

वित्त वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2022-23 तक देश में उद्योगों और घरों द्वारा खपत की गई बिजली का मिलियन यूनिट (एमयू) में ब्यौरा

वर्ष	घरेलू	विकास %	औद्योगिक	विकास %
2017-18	2,73,545.02		4,68,613.30	
2018-19	2,88,243.11	5.37	5,19,196.29	10.79
2019-20	3,08,745.00	7.11	5,32,820.00	2.62
2020-21	3,30,808.94	7.15	5,08,776.19	-4.51*
2021-22	3,39,780.47	2.71	5,56,480.96	9.38
2022-23	3,53,156.08	3.94	5,93,895.17	6.72

* कोविड समय
